



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175]

भोपाल, सोमवार, दिनांक.24 अप्रैल 2017—वैशाख 4, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

क्रमांक—एफ—3—100/2010/32 :: रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खण्ड (छ) के उप-खंड (चार) के साथ पठित धारा—84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी कोष नियम से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

अध्याय—एक प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रियल एस्टेट रेगुलेटरी कोष नियम, 2017 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एवं डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (2016 का 16);
 - (ख) “प्राधिकरण” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण;

- (ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण का अध्यक्ष;
- (घ) "कोष" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी कोष;
- (ङ) "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी कोष नियम, 2017।

3. कोष की स्थापना.—

- (1) कोष में निम्नलिखित रकम जमा की जाएगी—
 - (क) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त किया गया अनुदान।
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त की गई फीस।
 - (ग) खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट रकम पर प्राप्त किया गया ब्याज।
 - (घ) राज्य सरकार के आदेश से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।
- (2) प्राधिकरण द्वारा निधि की संक्रिया के लिए किसी अनुसूचित बैंक में बैंक खाता खोला जाएगा। कोष, प्राधिकरण के सदस्यों की एक समिति द्वारा प्रशासित होगा जैसाकि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए।
- (3) समिति उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए कोष का उपयोग करेगी जिसके लिए कोष गठित किया गया है।

4. कोष का उपयोग.—

कोष का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा :—

- (क) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय हेतु ;
- (ख) अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन के संदाय हेतु ;
- (ग) अपीलीय अधिकरण के प्रशासकीय व्ययों के भुगतान हेतु;
- (घ) अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में प्रोद्भूत कोई अन्य व्ययों के भुगतान हेतु।

5. बजट तैयार करना.—

- (1) प्राधिकरण वित्तीय वर्ष में उपगत होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करेगा।
- (2) प्राधिकरण बजट का उचित लेखा रखेगा तथा उसके अभिलेख का संधारण करेगा।
- (3) प्राधिकरण लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसाकि भारत के महालेखापरीक्षक की सहमति से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

6. बजट, लेखे तथा संपरीक्षा.—

- (1) प्राधिकरण बजट तैयार करेगा, उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे विहित प्ररूप में तैयार करेगा जैसाकि भारत के महालेखापरीक्षक की सहमति से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।
- (2) प्राधिकरण के लेखाओं का संपरीक्षण, महालेखापरीक्षक एवं भारत के नियंत्रक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें संबंधित वर्ष के क्रियाकलापों का विवरण सम्मिलित होगा। प्राधिकरण के संवीक्षित वार्षिक लेखाओं के साथ वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

7. विनियम बनाने की शक्ति.—

समिति, इन नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा विनियम बना सकेगी।

8. कोष का विघटन.—

कोष के विघटन की दशा में, सरकार विघटन के समय से कोष की समस्त आस्तियों की उत्तराधिकारी होगी।

9. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—

राज्य सरकार, समय-समय पर विसंगतियों, शंकाओं तथा कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से इन नियमों के उपबंधों से अनसंगत अनुदेश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल चन्द्र डाड, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

क्रमांक:-एफ-3-100/2010/32, :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/100/2010/32 दिनांक 24/4/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल चन्द्र डाड, उपसचिव.

Bhopal, the 24th April 2017

No.F-3-100/2010/32 :: In exercise of the powers conferred by section 84 read with sub-clause (iv) of clause (g) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following rules relating to Real Estate Regulatory Fund, Rules, namely:—

RULES

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement.-

- (1) These rules may be called the Real Estate Regulatory Fund Rules, 2017.
- (2) They shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
 - (b) “Authority” means the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority;
 - (c) “Chairperson” means the Chairperson of the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority;
 - (d) “Fund” means the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Fund;
 - (e) “Rule” means the Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Fund Rules, 2017.

3. Establishment of the Fund.-

- (1) The following shall be deposited in the fund-

- (a) The Grants received from the Central Government and the State Government.
 - (b) The fees received under the Act.
 - (c) The interest received on the amount referred to in clause (a) and (b).
 - (d) Any other amount received by the order of the State Government.
- (2) Authority shall open a bank account in any Scheduled Bank for the operation of the fund. The fund shall be administered by a Committee of members of the Authority as may be determined by the Chairperson.
- (3) The Committee shall utilize the Fund to carry out the objects for which the fund has been constituted.

4. Utilization of the Fund.-

The fund shall be utilized for the following purposes :-

- (a) for the payment of salary and allowances to the Chairperson, member, officers, employees of the Authority;
- (b) for the payment of salary to the officers and employees of the Appellate Tribunal;
- (c) for the payment of administrative expenses of the Appellate Tribunal;
- (d) for the payment of any other expenses accrued in discharging the functions of the authority for the purpose of the Act.

5. Preparing the Budget.-

- (1) The Authority shall prepare an annual budget to meet the expenses to be incurred in the financial year.
- (2) The authority shall maintain a proper account of the budget and shall maintain record thereof.
- (3) The authority shall maintain an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Auditor General of India.

6. Budget, Accounts and Audit.-

- (1) The Authority shall prepare a budget, maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such prescribed form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Auditor General of India.
- (2) The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or such Authority specified by him.
- (3) The Authority shall prepare an annual report in which a description of the activities of the concerned year shall be included. The Annual report along with the audited annual accounts of the Authority shall be submitted to the State Government for laying it before the State Legislative Assembly.

7. Power to make Regulations.- The Committee may by publication of this notification in the Official Gazette, may make regulations for the purposes carrying out the provisions of these rules.

8. Dissolution of the Fund.- In the event of dissolution of the Fund, The Government shall be the successor of all assets of the Fund at the time of dissolution.

9. Power to remove difficulties.- The State Government, may issue instructions not inconsistent with the provisions of these rules from time to time with a view to remove anomalies, doubts and difficulties.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GOPAL CHANDRA DAD, Dy. Secy.